सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 194 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार 21 अगस्त, 2026
मूल्य ₹ 3/-

केवल जब रंगों का उचित संतुलन होता है तो एक पेंटिंग बनती है। जीवन बस संतुलन के बारे में है।

-महात्रिया रा

टल सकता है भारतीय टीम का... 7 | बैड के जरिए गुड की जुगाड़ में... 3 | अपनी हार से बौखला गई भाजपा... 2

कॉकरोच से डरी राजस्थान की बीजेपी सरकार

राजस्थान में स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी टीम पर हमला

» सीजेपी की फाइडिंग भैसों के तबेलों में पढ़ रहे हैं राजस्थान के बच्चें

» आशुतोष रांका का बयान डंटे रहेंगे डरेंगें नहीं बीजेपी के लोगों ने हमला किया

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के जयपुर के रामपुरा कवंरपुरा गाव के सरकारी स्कूल का निरिक्षण करने पहुंची सीजेपी टीम की मौजूदगी से राजस्थान की राजनीति में ऐसा अलार्म बजा कि पहले गांव की सड़कों को सील कर दिया गया फिर सड़कों पर चल रही गाड़ियों की जांच हुई और उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई।

सवाल यह है कि आखिर सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के स्कूल निरीक्षण से राजस्थान की सरकार इतनी क्यों डर गयी। सीजेपी ने कहा है कि रामपुरा का सरकारी स्कूल लंबे समय से खराब हालत में जर्जर हो चुके स्कूल के बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाया जा रहा है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा है कि भैसों के तबलों में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है।

एक तरफ जर्जर स्कूल दूसरी तरफ सड़क पर नाकेबंदी

क्या कमाल का संयोग है बच्चों की पढ़ाई के लिए मजबूत छत नहीं है लेकिन स्कूल का निरीक्षण करने वालों को रोकने के लिए मजबूत इंतजाम जरूर कर लिया गया। जिस व्यवस्था को स्कूल की जर्जर दीवारें दिखाई नहीं दी उसे अचानक गांव की सड़कों पर चलती गाड़ियां दिखाई देने लगी। जिस प्रशासन को बच्चों की परेशानी का हिसाब लेना चाहिए था उसे अचानक यह पता लगाने की चिंता होने लगी कि कौन गांव में आ रहा है और कौन जा रहा है। यही वह तस्वीर है जो राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या अब विपक्ष या कोई राजनीतिक संगठन सरकार की नाक के नीचे जाकर सरकारी स्कूल की बदहाली दिखा देगा तो उसे रोक दिया जाएगा। बड़ा सवाल अगर स्कूल ठीक है तो निरीक्षण से डर क्यों? और अगर स्कूल ठीक नहीं है तो निरीक्षण रोकने की कोशिश क्यों।

कहानी सिर्फ इतनी नहीं है

सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जयपुर के एक गांव में सरकारी स्कूल देखने पहुंच गए। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। जिस स्कूल में बच्चों का भविष्य बनना था उस स्कूल की हालत पर सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी का दावा है कि स्कूल लंबे समय से खराब हालत में है और जर्जर भवन के कारण बच्चों को दूसरी

जगह पढ़ाया जा रहा है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया है कि बच्चे भैसों के तबेलों में पढ़ने को मजबूर हैं। अब अगर यह आरोप गलत है तो सरकार को गुस्सा किस बात का है आइए स्कूल दिखाइए कैमरे के सामने दिखाइए और कहिए कि देखिए राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था कितनी शानदार है। मगर स्कूल देखने वालों के रास्ते रोकना गाड़ियों की जांच करना और फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है।

सबकुछ जनता के लिए

सरकारें स्कूल बनाती हैं जनता के लिए। सड़कें जनता के लिए बनती हैं। सरकारी मशीनरी जनता की सेवा के लिए होती है। फिर जनता के नाम पर चलने वाली इसी व्यवस्था में जब कोई जनता के बच्चों के स्कूल की हालत देखने पहुंचता है तो इतनी बेचैनी क्यों दिखाई देती है? सवाल सीजेपी से भी पूछे जाएंगे सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे और सवाल उस पूरी व्यवस्था से भी होगा जिसने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए गए स्कूल को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर सीजेपी के आरोप गलत हैं तो सरकार के पास सबसे आसान रास्ता था स्कूल खोलो, कैमरा खोलो और सच दिखा दो। मगर अगर स्कूल की बदहाली सच निकली तो फिर सवाल सिर्फ रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का नहीं रहेगा। सवाल उठेगा कि राजस्थान के कितने स्कूलों की हालत ऐसी है? कितने बच्चे ऐसी जगहों पर पढ़ने को मजबूर हैं? कितने स्कूलों की जर्जर दीवारों के पीछे सरकारी दावों की चमक छिपी हुई है? अब राजस्थान की जनता को तय करना है कि वह इस कहानी में सड़कें सील होने की तस्वीर देखे या उस स्कूल की जर्जर दीवारें। क्योंकि स्कूल की दीवारें अगर कमजोर हैं तो सरकार मजबूत होने का दावा कैसे कर सकती है? और अगर सरकार इतनी मजबूत है तो फिर एक स्कूल का निरीक्षण उसे इतना बेचैन क्यों कर गया?

जारी रहेगा निरीक्षण अभियान

सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी के गुंडे हाथापाई पर उतर आये हैं। उनका कहना है कि सीजेपी का स्कूल निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि जिस स्कूल का आज निरिक्षण होना था उस स्कूल की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 12 लाख रूपये मंजूर किये जाने की बात सामने आ रही है। सवाल यह है कि जब बजट एलाट हो चुका था तो फिर काम क्यों नहीं शुरू हुआ और निरीक्षण के वक्त ही ऐसी बाते क्यों कि जा रही है। आशुतोष रांका ने कहा है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री कमियों को छिपाने के लिए हिटलरशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जबतक राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरती वह डंटे रहेंगे और डरेंगे नहीं।

क्या पहले लेनी होगी इजाजत!

राजस्थान में अब सरकारी स्कूल की हालत देखने के लिए भी इजाजत चाहिए क्या? जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सीजेपी की टीम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची तो ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल देखने नहीं सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ने पहुंच गया हो। पहले गांव की सड़कें सील की गयी फिर रास्तों पर दौड़ती गाड़ियों की जांच की गयी उसके बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं से कहासुनी और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। यानी स्कूल की छत जर्जर हो सकती है दीवारें टूट सकती हैं बच्चे दूसरी जगह पढ़ सकते हैं लेकिन कोई उन टूटती दीवारों की तस्वीर लेने पहुंच जाए तो पूरी व्यवस्था की नसों में बिजली दौड़ जाती है। सवाल सीधा है आखिर राजस्थान की बीजेपी सरकार को स्कूल से डर है या स्कूल की सच्चाई से?

अपनी हार से बौखला गई भाजपा : अखिलेश यादव

मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के सपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा प्रहार किया है। मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी की पिटाई मामले को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार डर से बौखला गई है। बात दें मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी को कथित पुलिस हिरासत में लेकर मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से इतनी बौखला गई है कि किसान नेताओं को थर्ड डिग्री की मारपीट कर प्रताड़ित करवा रही है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने लिखा–किसान का अपमान, देश का अपमान है! भाजपा ने किसान के मुंह पर लात मरवाकर पूरे देश के किसानों को धमकाने का जो कुकृत्य किया है वो अक्षम्य है।

उप्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान नेताओं पर थाने में थर्ड डिग्री की मार-पीट करके प्रताड़ना देना दर्शाता है कि हार के डर से वो कितनी बौखलाई है। जिन्हें भाजपा किसानों के आगे ढाल बनाकर साथ में खड़ा करना चाहती थी वो ढाल भी निम्नलिखित कारणों से, किसानों के आक्रोश की आग के कारण मोम की ढाल ही साबित हुई है।

भाजपा सरकार पर बरसे सपा मुखिया

कुछ लोगों के हाथ में खेती-किसानी, भंडारण, विदेशी बीज-खाद- पैदावार का व्यापार-विपणन देने के लिए विदेशियों से डील करती है। एमएसपी के लिए तैयार नहीं होती है। ख़रीद के लिए मुकर जाती है। खाद की अंतहीन लाइन में किसानों को लगाती है। भूमि अधिग्रहण व तीन काले क़ानून लाकर, किसानों का सब कुछ हड़प लेना चाहती है। किसान आंदोलन में 700 से भी अधिक किसानों की शहादत पर चुप रहती है।

ये है पूरा मामला

बता दें कि भारतीय किसान यूनियन बीयर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने मेरठ पुलिस और एसओजी की टीम पर उन्हें हिरासत में लेकर मारपीट और थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया था. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें उनके चेहरे पर गंभीर चोटें दिखाई दे रही हैं. वहीं मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे इन आरोपों से इनकार किया है. इस बीच एसएसपी अविनाश पांडे का देर रात ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है।

किसानों की आत्महत्याओं पर शोक तक प्रकट नहीं करती है

किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मारनेवाले अपने लोगों का क्लीन चिट देती है। उस भाजपा सरकार से इससे अधिक उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो किसानों के हित के नाम पर उनके तथाकथित हितैषियों से समझौता करके अपनी स्वार्थ सिद्धी में लगी रहकर 'किसान नेताओं' को थर्ड डिग्री देगी और कुछ नहीं। देश भर के किसान देख लें कि भाजपा और उसके सहयोगी किस तरह सत्ता सुख में लीन रहकर किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं इस मामले की गहरी जाँच हो और हर दोषी के खिलाफ़ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और बर्खास्तगी भी।

25 साल तक न बदली जाएं लोकसभा की सीटें : चिदंबरम

परिसीमन पर सीएम विजय को कांग्रेस का समर्थन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत की राजनीति गरमा गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने तमिलनाडु सरकार और अन्य क्षेत्रीय दलों के रुख का समर्थन करते हुए लोकसभा सीटों की मौजूदा स्थिति को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखने की मांग की है। चिदंबरम ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी संसद की कुल 543 सीटों और तमिलनाडु की 39 सीटों के आवंटन में कोई बदलाव नहीं चाहती।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर साझा की गई एक पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु विधानसभा और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव इस साझा रुख को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुल क्षमता 543 सीटों और तमिलनाडु के 39 निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सीटों के इस मौजूदा आवंटन को अगले 25 सालों तक यथावत रखा जाना चाहिए। चिदंबरम ने इस बात पर भी खुशी जताई कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ टीवीके और मुख्य विपक्षी दल डीएमके दोनों इस रुख का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने उठाई थी चिंता

यह घटनाक्रम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 पर जताई गई गहरी चिंताओं के ठीक एक दिन बाद सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री विजय ने चेतावनी दी कि यदि सीटों का पुनर्वितरण मुख्य रूप से आबादी के आधार पर किया जाता है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को न मिले सजा : परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में बोलते हुए मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से यह आश्वासन मांगा कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित और स्थिर किया है, उन्हें उनके संसदीय प्रतिनिधित्व में कटौती करके दंडित न किया जाए।

पंजाब के विकास के लिए दिल्ली जरूरी : हरसिमरत

शिअद नेता ने भाजपा के साथ गठबंधन की अटकलों को हवा दी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की तरक्की के लिए दिल्ली से बेहतर संबंध की इच्छा जताकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है।

सांसद ने यह संकेत यहां संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की शहादत की 41वीं बरसी के मौके पर आयोजित शिअद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा, 'गुरु साहिब कृपा करें। बोलना मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी जुबान रोक रही हूं। आपको खुद ही पता चल जाएगा।' हरसिमरत ने कहा, 'ईश्वर हम पर कृपा करें और लोग हमें हिम्मत दें। ऐसे समझौतों के जरिए, जिनसे विकास और तरक्की से जुड़े काम दिल्ली से किए जाते थे, एक बार फिर पंजाब में उसी विकास और तरक्की की नींव रखी जा रही है, जिससे पंजाब और पंजाब के लोगों को लाभ होगा।

इस महीने की शुरुआत में, शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से शिअद के भाजपा के साथ गठबंधन करने की अटकलें शुरू हो गई थीं। शिअद पहले भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा था लेकिन अब रद्द हो चुके तीन कृषि कानूनों को लेकर वह गठबंधन से अलग हो गया था।

इमरान मसूद को बड़ा झटका, दामाद शायान मसूद सपा में शामिल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सांसद के दामाद शायान मसूद कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शायान मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में गाना भी लगाया।

इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर जानकारी देते हुए बताया कि आज लखनऊ में सहारनपुर के शादान मसूद, शायान मसूद एवं उनके साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद के दामाद का सपा में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद और सपा नेता शायान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं कि पीडीए की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर उत्साह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आए। हम लोग भी पार्टी के साथ और पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इंशाअल्लाह मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद और सपा नेता शायान मसूद ने कहा कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के सबसे दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच वाले नेताओं में से एक हैं।

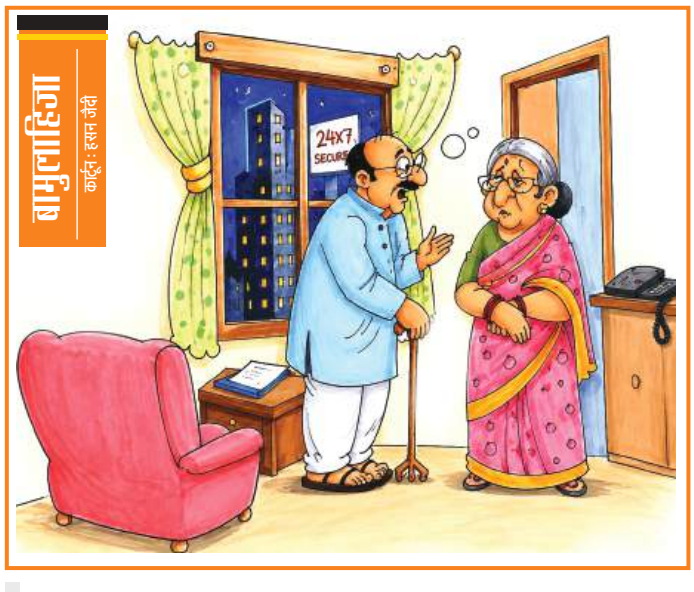

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेंगे : फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बीजेपी पर बरसे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने क हा कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है और उनकी पार्टी इसके लिए संघर्ष कभी नहीं छोड़ेगी।

एक बयान में अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष संवैधानिक दर्जा संघ के साथ उसके विशिष्ट और अद्वितीय संवैधानिक संबंध को दर्शाता था और यह विरासत नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में बनी हुई है। पार्टी प्रमुख ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को भले ही ''एकतरफा तरीके से बदल दिया गया'' हो, लेकिन उनकी पार्टी उनकी बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा, ''यह मुद्दा पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए आवाज उठाने का अधिकार है।

बैड के जरिए गुड की जुगाड़ में सियासत

नेताओं की नजर जातियों के समीकरण पर

- ब्राह्मण-अल्पसंख्यक-दलित- बीएडी को रिझाने की तैयारी
- सपा-बसपा-कांग्रेस से मिल रही भाजपा को चुनौती
- सहयोगी दलों के तेवर भी बीजेपी को पड़ेगा भारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। जैसे-जैसे 2027 करीब आ रहा है वैसे-वैसे यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जहां सत्ता में बैठी भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व के सहारे चुनावी वैतरनी पार करना चाहती है। वहीं विपक्षी पार्टियां जाति का समीकरण व अल्पसंख्यकों के सहारे भाजपा को सत्ता से हटाकर खुद काबिज होने की रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलकार भाजपा हिंदुओं के वोट को गांठे रहना चाहती है तो विपक्ष ब्राहमण, अल्पसंख्यक, दलित-पिछड़ा मतलब बीएडी अर्थात बैड के सहारे 27 में अच्छे दिन-गुड की फिराक में लगा है।

अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा किसका दांव चला और कौन नाकाम रहा। फिलहाल सभी पार्टियां चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या छोटे दल अलग-अलग जातियों को रिझाने में लगी हैं। सबसे ज्यादा पंडित, दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वोटरों पर सबकी नजर है। इसलिए सभी सियासी दल इनको अपने संगठन से लेकर मंच तक साधने के लिए इनके बारे में बोलने में शब्दों की कंजूसी नहीं कर रहे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती का ने यूपी चुनाव के लिए सतीश चंद्र मिश्रा का कद बढ़ाया हैं। वहीं सपा प्रमुख पीडीए में पी को पंडित बता रहे हैं। तो कांग्रेस व भाजपा भी दांव लगाने में पीछे नही हट रहे हैं। उधर भाजपा के सहयोगियों ने उस पर दबाव भी बनाना शुरूकर दिया है।

यूपी में 10 प्रतिशत से ज्यादा ब्राह्मण वोटर

राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 10 से अधिक पर ब्राह्मणों का व्यापक असर है और किसी न किसी तरह से यह लगभग पूरे प्रदेश को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कोई भी पार्टी इस समाज की अनदेखी करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की 37 सीटों पर जीत में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) ने भूमिका निभाई थी, लेकिन पार्टी को एहसास है कि केवल पीडीए के सहारे विधानसभा चुनाव में सत्ता पाना आसान नहीं है, इसलिए अब पीडीए की छतरी के नीचे ब्राह्मण समेत दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश है। पिछले दिनों जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश ने पीडीए में पंडित को पंडित से जोड़कर राजनीति को नया मोड़ दिया। ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश के इस नये कदम पर रणनीतिकारों का मानना है कि यदि पीडीए संग ब्राह्मणों का एक हिस्सा भी जुड़ता है तो विधानसभा चुनाव की मौजूदा तस्वीर बदल सकती है।

ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा अब भी बीजेपी के साथ

विपक्ष, ब्राह्मणों में कथित नाराजगी की चर्चाओं को भी हवा दे रहा है। विपक्षियों की इस तरह की कोशिश भाजपा की बेचैनी बढ़ाने वाली है। ब्राह्मण, भाजपा का मजबूत सामाजिक आधार रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद से इस वर्ग का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ रहा है। कुछ समय से समाज की नाराजगी की चर्चाओं के बीच चढ़ावा चोरी आदि मामलों ने भी चुनौती बढ़ाई है। हालांकि, भाजपा के खासतौर से ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि पार्टी पर ब्राह्मणों का भरोसा कायम है। भरोसा बढ़ाने के लिए पार्टी ब्राह्मण बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों और धार्मिक संस्थानों से संवाद बढ़ाने की रणनीति पर भी तेजी से काम करती दिख रही है।

ब्राह्मण वोट से जीत का फॉर्मूला तलाश रही सपा

ब्राह्मणों को साधने के लिए पहले से जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब पीडीए में पीडी को पिछड़ा-दलित के साथ अब पंडित का भी शॉर्ट फॉर्म बताकर अपनी रणनीति साफ कर चुके हैं। अखिलेश की कोशिश पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) संग ब्राह्मणों की सोशल इंजीनियरिंग से बसपा की तरह एक दशक बाद सत्ता हासिल करने की है। पहले की तरह ब्राह्मणों का फिर आशीर्वाद पाने को मायावती भी सक्रिय हैं, इसलिए हैट-ट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने अपने परंपरागत आधार को इस बार एकजुट रखने की बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता 10 प्रतिशत से ज्यादा माने जाते हैं। वोटरों से ज्यादा चुनावी समीकरण में ब्राह्मण समाज सदैव अहम भूमिका निभाता रहा है।

बसपा ने ब्राह्मण समाज को 2007 से खास तवज्जो दिया था

मायावती ने कहा कि बीएसपी ने सर्वसमाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को 2007 से खास तवज्जो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले के बाद से विरोधी पार्टियों में इसको लेकर चर्चा व चिन्तायें हैं। जिनके हथकण्डों से 'बहुजन समाज' के लोगों को लगातार सजग व सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सतीश चन्द्र मिश्र को पार्टी द्वारा लीगल व मीडिया आदि के साथ-साथ अब चुनाव आयोग सम्बंधी कार्यों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जो कि खासकर आगामी विधानसभा आमचुनाव के दौरान कई मायने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। सतीश चन्द्र मिश्र बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता व बीएसपी सरकार में यूपी के महाधिवक्ता भी रहे हैं। मिश्र यूपी बार काउन्सिल के कई बार और बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री के अलावा राज्यसभा सांसद भी रहे हैं।

भाजपा ने नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो जाएगी : संजय निषाद

संजय निषाद ने निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने निषाद समाज की बात नहीं सुनी तो वो भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जैसे यूपी से सपा, बसपा और काँग्रेस सत्ता से बाहर चले गए। इस दौरान आरक्षण को लेकर अपनी बात रखते हुए संजय निषाद ने ये बात कही। यूपी के मंत्री ने इस दौरान कहा कि उनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, देश का आजाद कराया और संविधान भी लिखवाया है। संजय निषाद ने मंच से कहा कि निषाद एक अपील करता है निषाद की एक अपील है, जिसे हाथी साइकिल और पंजा ने नहीं सुना तो सत्ता से बाहर चले गए अगर भाजपा भी नहीं सुनेगी तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी अपील एकदम सही है। हमारे पूर्वजों ने देश आजाद करवाया, पूर्वजों ने संविधान लिखाया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा

कि जब तक निषाद समझ को उसका हक और आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगी। संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने दस साल पहले निषादों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल किए जाने का संकल्प लिया था और कहा कि था कि जब तक निषाद को एससी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता तब तक वो ना खुद बैठेंगे और आपको बैठने देंगे।

बसपा और सपा में भी टक्कर

अखिलेश के इस कदम की राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भाजपा और बसपा ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। भाजपा ने सपा सरकारों के कार्यकाल और ब्राह्मणों से जुड़े सवाल उठाकर पलटवार किया तो बसपा ने भी सपा पर निशाना साधा। यानी एक बयान ने भाजपा और बसपा को भी अपने-अपने सामाजिक आधार को सक्रिय करने का अवसर दे गया। साफ है कि सत्ता के लिए सपा जहां पीडीए की छतरी बड़ी करना चाहती है तो बसपा दो दशक पुरानी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता में वापसी तलाश रही है। वर्ष 2007 की तरह ब्राह्मणों का फिर साथ पाने के लिए मायावती पार्टी संगठन से लेकर टिकट देने में ब्राह्मणों को जगह देती दिख रही हैं। चूंकि ब्राह्मणों पर सपा-बसपा, दोनों की नजर है, इसलिए मुकाबला केवल भाजपा से नहीं बल्कि एक-दूसरे से भी है।

मायावती ने खुद संभाली कमान

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी में विधानसभा 27 की तैयारियों को लेकर बीएसपी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के लिए जमीन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ–साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन व

उनके नामों की पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा करने आदि की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों में भी अब अनवरत बदलाव होना भी स्वाभाविक है।

कई जिम्मेदारियां संभालेंगे सतीश चन्द्र मिश्र

मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 27 से पहले यूपी में बड़ा दांव चला है। मायावती ने सतीश चन्द्र मिश्र को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मिश्र लीगल व मीडिया के साथ-साथ अब चुनाव आयोग सम्बंधी काम भी देखेंगे। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि सतीश चन्द्र मिश्र की यूपी चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। मायावती ने

कहा है कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जुट गई है। इसके लिए बसपा सभी समाज के लोगों के लिए जमीन पर मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बसपा की तैयारियों से विरोधी दलों में बैचेनी बढ़ी है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

यात्री सुविधाओं की अनदेखी चिंताजनक

सरकार दावा करती है कि उसने हर क्षेत्र में विकास की बाढ़ ला दी है। वैसा ही दावा रेलवे में भी किया गया है पर अभी कैग की जो रिपोर्ट आई है उसने सब पोल खोल के रख दिया है। रेल का सफर चाहे लंबी दूरी का हो या छोटी दूरी का। यात्रियों को पीने के पानी की सदैव जरूरत रहती है। इसीलिए हर छोटे-बड़े स्टेशन पर यात्री प्लेटफॉर्म पर बने वाटर कूलर से पीने के पानी का इंतजाम करके सवारी गाड़ी में चढ़ते हैं। यात्री सुविधाओं की कहीं भी अनदेखी चिंताजनक है। स्टेशनों पर ठहराव होते ही पहले से बैठे यात्रियों की दौड़ भी वाटर कूलर की तरफ होती है ताकि आगे के सफर के लिए पानी का बंदोबस्त हो सके। चिंता की बात यह है कि यात्रियों की इस सबसे बड़ी जरूरत के मामले में ही उनकी सेहत से खिलवाड़ होता दिख रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है। इस रिपोर्ट से रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई और यात्रियों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है।

वह इसलिए भी क्योंकि रिपोर्ट मेंकेवल पीने के पानी के दूषित होने की बात ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर शौचालयों की बदहाली का भी उल्लेख किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर लगे वाटर कूलरों के पानी की जांच में जो बैक्टीरिया मिला है, वह लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। ऐसे में यात्रियों के बीमारी मोल लेने का खतरा बढ़ गया है। जरूरी नहीं कि हर यात्री बोतलबंद पानी खरीदने की क्षमता रखता हो। रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वह यात्रियों को पीने का साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराए। रेलवे स्टेशन पर खान-पान सामग्री तैयार करने वाली स्टॉलों पर भी इसी पानी का इंतजाम होता है। ऐसे में जो खाद्य सामग्री बन रही होगी वह भी गुणवत्ता के मापदंड पर कितनी खरी उतरेगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कैग की जांच रिपोर्ट तो महज 512 रेलवे स्टेशनों की ऑडिट के नतीजों पर आधारित है। इनमें से 498 स्टेशन न्यूनतम सुविधा मानकों पर भी खरे नहीं उतरे तो चिंता बढनी स्वाभाविक है। हैरत की बात यह है कि इनमें से 59 रेलवे स्टेशनों पर तो पानी की जांच तक नहीं की गई, जबकि पानी की गुणवत्ता जांच बंदोबस्त अनिवार्य होने संबंधी स्थायी आदेश पहले से ही लागू हैं। सवाल सिर्फ पीने का पानी के साफ होने का ही नहीं है, रेलवे में आधुनिकीकरण के तमाम प्रयास उस समय मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं, जब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा संबंधी मूलभूत जरूरतों तक की अनदेखी नजर आती है।

> **“ चिंता की बात यह है कि यात्रियों की इस सबसे बड़ी जरूरत के मामले में ही उनकी सेहत से खिलवाड़ होता दिख रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है।**

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

हर रोज हो 'ना' कहने की आजादी

ज्योति मल्होत्रा

पिछले कुछ हफ्तों में, महिलाएं एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं, कि उन्हें क्या कहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। सबसे ऊपर यह कि जब कोई महिला 'न' कहे, चाहे धीरे से या जोर से तो पुरुष रुकते क्यों नहीं? पितृसत्ता के बारे में सदियों से बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हालिया 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के दौरान लगे नारे, या कोई एक खबर रही जिसने इस शब्द की जटिलता को बखूबी बयां किया। जो इंस्टाग्राम पर भी खूब छाई रही एक युवती कह रही थी कि अपनी मां को विरोध-प्रदर्शन में लाने से डरें नहीं कि आंसू गैस का गोला लगने पर वह रो पड़ेंगी; क्योंकि पितृसत्ता ने उनके सारे आंसू पहले ही सुखा दिए हैं। तंजयुक्त छोटे से इस गंभीर वाक्य में, इस महिला प्रदर्शनकारी ने हमें गहन मंथन को बाध्य किया। हम घर-बाहर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मानो उनकी कोई आवाज ही न हो और न ही आवाज उठाने की क्षमता?

हमने वह वीडियो देखी हैं जिसमें 20 जुलाई को संसद तक हुए सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में पुलिसकर्मी एक युवती से लाठी से अक्षम्य कृत्य कर रहा था और एक पुरुष आईपीएस अधिकारी एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मार रहा था। अब तक कई मीडिया माध्यमों पर उन युवतियों के इंटरव्यू सुने हैं, जिन्होंने बताया कि विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन्हें किस तरह की गालियों और बदसलूकी का सामना करना पड़ा जिनमें से ज्यादातर यौन-उत्पीड़न से जुड़ी थीं। हमने सुना है कि कैसे कई महिलाओं की पहचान उनकी मर्जी के बिना सार्वजनिक कर दी गई- इसको लेकर हमारी शब्दावली में नया शब्द 'डॉक्सिंग' शब्द शामिल हुआ था; यह शब्द 1990 के दशक की शुरुआत में पश्चिम की हैकर संस्कृति से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी दस्तावेज को 'ड्रॉप' करना या साझा करना और कैसे इन महिलाओं को तंग किया गया और धमकियां दी गईं, क्योंकि आरोपी पुरुष, जो कि पूरी तरह अनजान थे, उन्हें लगा कि इन महिलाओं को उनकी 'औकात' दिखाना जरूरी है।

ऐसे समय में 2012 में वीभत्स निर्भया गैंगरेप को याद किए बिना नहीं रहा जा सकता उसका असली नाम ज्योति था, और अब हम उसका नाम ले सकते हैं क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं है तब दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं उतरी थीं और विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का सामना किया था। लगभग दस दिन पहले, हमने 2013 के तरुण

तेजपाल मामले में पीड़िता की मां के शुक्रगुजार शब्द पढ़े थे जब बॉम्बे उच्च न्यायलय की गोवा बेंच (जिसमें एक महिला जज शामिल थीं) ने गोवा की निचली अदालत के 21 के फैसले को पलट दिया था निचली अदालत का वह फैसला भी एक महिला जज ने ही सुनाया था, जिसमें उन्होंने तेजपाल को एक लिफ्ट में पीड़िता के साथ रेप के आरोप से बरी कर दिया था। सोचिए तब एक मां पर क्या बीती होगी जब उसकी बेटी की गुहार अनसुनी रह जाती है, जब उसकी बेटी 'न' कहती है, और सामने वाला आदमी उस पर कान धरने से इनकार कर देता है। यह समझने हेतु किसी को महिलावादी होने की जरूरत नहीं है कि गाली-गलौज की शब्दावली ज्यादातर महिलाओं खासकर बहनों और माताओं के अपमान पर ही क्यों टिकी होती हैं, या क्योंकर यौन शोषण, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और रेप हिंसा के हथियार हैं। ये बातें तो बहुत पुरानी हैं। परेशानी की बात यह है कि 21वीं सदी में भी यह नियंत्रण बरकरार है। जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत' बनने और एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभरने की ओर बढ़ रहा है, सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों द्वारा महिलाओं के शरीर-मन पर नियंत्रण बनाने की जरूरत और बलवती होती दिख रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को हाल ही में एक निचली अदालत ने कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है बरी होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और एनडीटीवी की एक साहसी युवा महिला पत्रकार का मुंह पर मजाक उड़ाया, जो उनसे सख्त सवाल पूछ रही थी। तभी तो महिलाएं उत्तरोत्तर उस हथियार का सहारा लेने को अग्रसर हैं, वे जानती हैं कि वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगा।

इसीलिए आपको जंतर-मंतर और रांची में हर विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा पोस्टर अंबेडकर के दिखाई देते हैं। गांधी, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस के भी होते हैं लेकिन उतने नहीं। केवल अंबेडकर ही, एक दलित, जिन्होंने अपनी मुश्किल परिस्थितियों से उबरकर संविधान लिखने का नेतृत्व किया, यह समझते थे कि जाति और धर्म से परे सभी महिलाओं और पुरुषों को समानता और न्याय का अधिकार देना क्यों जरूरी है। वे जाति के नाम पर होने वाली हिंसा को समझते थे याद रखिए कि जाति जीवन भर आपका पीछा करती है ।

इस्लामिक नाटो के ख्याली किले और हकीकत

पुष्परंजन

गुजिश्ता शुक्रवार को दुनिया के तीन सुर्खियों में रहने वाले मुस्लिम देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से जो सुरक्षा समझौता हुआ है, वह उस चीज से अभी बहुत दूर है जिसे कई लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। विश्लेषक मक्का समझौते का मकसद समझने का प्रयास कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब, नाटो सदस्य तुर्की और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, उसकी वजह धार्मिक है या अज्ञात भय? सुन्दरकाण्ड के श्लोक का एक हिस्सा याद कीजिये— 'भय बिनु होइ न प्रीति।' तुर्की के वरिष्ठ राजनयिक हाकान फिदान ने कहा कि मक्का समझौते में यह अहद किया गया है कि तीनों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमले को सभी पर हमला माना जाएगा; यह बात तकनीकी रूप से ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा गठबंधन के अनुच्छेद 5 में बताए गए रक्षा सिद्धांत जैसी ही है।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है, बशर्ते समझौते में शामिल देशों पर हमला न किया जाए। यों, इस समझौते का तेहरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। भारत ने किसी तरह की चिंता प्रत्यक्ष रूप से ज़ाहिर नहीं की है, लेकिन नई दिल्ली को ऐसे गठबंधन को काउंटर करने की जरूरत तो है। जानकारों ने इस समझौते को लेकर उम्मीदें कम रखी हैं। जानकार, इस क्षेत्र में एक टिकाऊ रक्षा गठबंधन बनाने की पहले की गई ऐसी ही कोशिशों की ओर इशारा करते हैं, जो ज्यादा समय तक नहीं चल पाईं। चीन के 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस' में मिडिल ईस्ट इकोनॉमी एंड एनर्जी स्टडीज के निदेशक थांग थियानबो ने कहा कि यह गठबंधन 'अभी भी नाटो जैसे सैन्य गठबंधन से बहुत दूर है'। आज से 26 साल पहले, दिसंबर, 2000 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के छह सदस्यों के बीच हुए संयुक्त रक्षा समझौते को भी कुछ लोगों ने 'गल्फ नाटो' कहा था। कई बार संयुक्त सैन्य तैनाती भी की गई थी। हालांकि, 2017 में सहयोग प्रयास रुक गए जब कई सदस्य देशों ने कतर के साथ संबंध तोड़ दिए। बाद के संकटों में इस समूह की प्रतिक्रिया काफी हद तक राजनयिक बयानों तक सीमित रही।

निंगजिया विश्वविद्यालय में चीन-अरब अनुसंधान संस्थान के निदेशक नी शिनचुन भी मानते हैं कि मक्का समझौते को 'इस्लामिक नाटो' कहना 'निश्चित रूप से अतिशयोक्ति ' है। रियाद और इस्लामाबाद ने पिछले साल 17 सितंबर को एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साल भर के भीतर तुर्की भी इस गठबंधन में शामिल हो गया। 7 अगस्त, 2026 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 'संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किये। मक्का समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो दिन बाद, यमन में ईरान समर्थित हूथी समूह ने देश के दक्षिण-पश्चिम में सऊदी तेल रिफाइनरी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान और तुर्की ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मिडिल ईस्ट पर केंद्रित वॉशिंगटन की कंसल्टेंसी रिहला रिसर्च एंड एडवाइजरी के फाउंडर जेसी मार्क्स ने कहा कि इस समझौते के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि हर सदस्य अलग-अलग खतरों से बचाव को प्राथमिकता देता है। उनकी नज़र में तीनों सदस्यों की सुरक्षा प्राथमिकताएं काफी अलग-अलग हैं - रियाद का ध्यान ईरान और खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरों पर है, तुर्की को इस्राइल की चिंता है, जबकि पाकिस्तान भारत, अफगानिस्तान और घरेलू स्थिरता को प्राथमिकता देता है। समझौते के तहत हमले का क्या मतलब है? इसका जवाब जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है ताकि तीनों पक्षों को अपनी रणनीति तय करने की पूरी आजादी मिल सके। अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान पहले से इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि कौन, कहां और किन हालात में लड़ेगा, तो मक्का समझौता सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान की घरेलू हालत जर्जर है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वित्तीय बदहाली को दूर करने की बजाय प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ विश्व नेता बनने की रेस में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का इस्लाम इसलिए जगता है, ताकि वह विश्व कूटनीति में अलग-थलग न पड़ जाये। हालांकि ऐसी शंकाओं पर सऊदी अरब के पब्लिक डिप्लोमेसी मामलों के डिप्टी मिनिस्टर रायद क्रिमली ने कहा, 'सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता किसी 'सैन्य धुरी या सांप्रदायिक गुट' को बनाने की कोशिश नहीं है।

और न ही इसका संबंध किसी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा या हथियारों की होड़ से है, बल्कि यह टिकाऊ क्षमताएं विकसित करने पर केंद्रित है।' यदि इस्लामिक कार्ड का कोई रोल नहीं है, तो पाकिस्तान-तुर्की-अज़रबैजान किसलिए नये गठबंधन में आगे बढ़े? इसी हफ्ते अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस्लामाबाद और बाकू के बीच बढ़ते संबंधों पर ज़ोर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान-तुर्की-अजरबैजान के बीच तीन देशों वाले 'ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क' के तहत बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया है। अजरबैजान का पाकिस्तान और तुर्की के साथ गहरा रक्षा व रणनीतिक गठजोड़ है, और वह कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान, सेन्ट्रल एशियाई देशों को ग्वादर और कराची पोर्ट के जरिए दुनिया के बाजारों से जोड़कर एक 'ट्रांजिट हब' बनना चाहता है। इस मकसद के वास्ते धर्म, एक प्रच्छन्न हथियार के रूप में काम कर रहा है।

अंजीर

फाइबर और विटामिन्स से होता है भरपूर

सेहतमंद शरीर चाहते हैं तो आहार में उन चीजों को अधिक से अधिक शामिल करें जिनसे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अंजीर ऐसा ही एक बेहद फायदेमंद सूखा फल और मेवा है जिसे बेहद गुणकारी माना गया है। यह स्वाद में मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। सूखे और ताजे दोनों रूपों में अंजीर का सेवन किया जाता है और खास बात यह है कि इसमें मौजूद पोषक तत्वों की हमारे शरीर को नियमित रूप से जरूरत होती है । फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अंजीर न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव में मदद करता है। अंजीर के पानी के सेवन से महिलाओं में होने वाले हॉर्मोनल असंतुलन ठीक हो जाते हैं। इससे पीरियड नियमित होते हैं।

पेट के लिए है फायदेमंद

अंजीर में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स और पॉलीफेनॉल्स शरीर में सूजन कम करने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं। रोजाना सीमित मात्रा में अंजीर खाने से शरीर को जरूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। अंजीर में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंतों की कार्यप्रणाली को सुधारता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। अंजीर के पानी के लैक्सेटिव गुण सुबह पेट साफ होने में मदद करते हैं। अंजीर के पानी का नियमित सेवन करने से भूख नियंत्रित होती है। इस पानी में मौजूद फाइबर पेट की समस्याओं जैसे गैस, कब्ज या अपच में राहत देता है। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और आंतों की सफाई भी हो जाती है।

हड्डियों को करे मजबूत

अंजीर कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। ये पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। अंजीर में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये त्वचा को फ्री-रेडिकल डैमेज से बचाकर उसे हेल्दी बनाए रखने में मददगार है। अंजीर को हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें पोटैशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है।

ब्लड प्रेशर रखे संतुलित

आयुर्वेद में अंजीर को बेहद लाभकारी फल माना जाता है। अंजीर के पोषक तत्वों का लाभ उठाने के लिए आप अंजीर को रातभर के लिए पानी में भिगो दे और सुबह अंजीर के साथ इसके पानी का भी सेवन करें। इससे सभी पोषक तत्व शरीर में सही तरीके से अवशोषित होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद पोटैशियम शरीर में सोडियम (नमक) के प्रभाव को कम करने और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करती है। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। अंजीर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की धमनियों को स्वस्थ रखने में भी सहायक माना जाता है। इससे आप ओवरइटिंग करने से बचते है यह पानी वजन कम करने में भी मदद करता है। इस पानी में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। इससे थकान और कमजोरी दूर होती है। इन्हें खाने के लिए रात में 2-3 सूखे अंजीर को एक कप पानी में भिगो दें। अगली सुबह खाली पेट इनका सेवन करें और वह पानी भी पी लें। या एक गिलास दूध में 2-3 अंजीर डालकर उबाल लें और रात में सोने से पहले इसका सेवन करें।

डायबिटीज में भी खा सकते हैं अंजीर

अंजीर मीठा होता है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका डायबिटीज में सेवन किया जा सकता है? अध्ययनों से पता चलता है कि सीमित मात्रा में सेवन करने पर इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ने में मदद करता है, जिससे शुगर स्पाइक्स का खतरा कम होता है। हालांकि ज्यादा सेवन से शुगर बढ़ने का खतरा हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर किडनी स्टोन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और लेटेक्सएलर्जी की समस्या है, वे चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही अंजीर या इसके पानी का सेवन करें।

हंसना मना है

शादी की सालगिरह पर पत्नी को गुलाब देते हुए पति बोला, सालगिरह मुबारक हो! पत्नी- यह नहीं मुझे कोई सोने की चीज चाहिए। पति- ओ, यह लो तकिया और आराम से सो जाओ।

टीचर- बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क है? स्टूडेंट- कंडक्टर सोया तो किसिका टिकट नहीं कटेगा, ड्राइवर सोया तो, सबका टिकट कट जायेगा।

लड़का- डिअर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे जल्दी से बताओ!' लड़की -'सच्चा प्यार' लड़का -'oye! सच्चा प्यार की बच्ची कचरा गया है जल्दी फूंक मार।

आपने कभी सोचा है, की पति और चाय की पत्ती में क्या समानता है? दोनों के नसीब में जलना और उबालना लिखा है और वो भी औरतों के हाथ से।

बच्चा मेडीकल वाले से- अंकल, गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मेडिकल वाला - हां है.. शरारती बच्चा- तो लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देखकर डर जाता हूं!

डॉक्टर- पप्पू अब तुम्हारी पत्नी कैसी है? पप्पू- अब काफी सुधार है उसकी तबियत में, आज सुबह तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी की उसने।

कहानी | शांति कहां मिलेगी

एक समय कि बात है, भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ चीजें भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते और खुशी-खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते। जब सब चले गए तो उनकी चरण सेविका श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा- हे नाथ! मैंने देखा कि आपने सभी को कुछ न कुछ दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा लेकिन एक चीज आपने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया है। वो चीज क्या है? श्री हरि मंद-मंद मुस्कुराते रहे, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने फिर कहा- प्रभु हमसे न छुपाएं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है आपने कोई एक चीज अपने पैरों के नीचे छिपा रखा है, निवेदन है कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। श्री हरि बोले- देवी मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति मैंने किसी को नहीं दिया, सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती हैं मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास ही होगी। मैं सब को नहीं दे सकता। जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर्य होगा, जिसकी सारी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होगी, उसी को ये मिलेगा। श्री हरि से आज्ञा लेकर शांति कहने लगी- हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया बल्कि मैं स्वयं उनके पैरों के नीचे छिप गई। शांति तो सिर्फ़ हरि चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं। **कहानी से सीख**- कथा कहती है कि उसी दिन से श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि के चरणों की सेवा शुरू कर दी, क्योंकि व्यक्ति सारी सुख सम्पत्ति से सुसज्जित हो मगर उसके पास शांति ही न हो तो उसकी सारी सुख सम्पत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी भी शांति प्राप्ति हेतु और श्री हरि सेवा के लिए उनके चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। इसलिए भगवान की चरण सेवा करें, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें। निस्वार्थ सबका भला करें और परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखें।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबारी हैं तो प्राथमिकताओं के आधार पर काम निपटाएं। जरूरी कागजातों को संभालकर रखें।

वृषभ

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी। नए सौदे लेने या प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का सही समय है। संबंधों में ताजगी और सकारात्मकता महसूस होगी।

मिथुन

अपनी संवाद क्षमता का सही इस्तेमाल करें। व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर के साथ दिल खोलकर बात करने से पुरानी कड़वाहट खत्म होगी।

कर्क

कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी भी बहस से दूर रहें। कारोबार में फिलहाल बड़ा निवेश टाल देना ही समझदारी है। अनियोजित खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है।

सिंह

काम का दबाव रहेगा, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें। व्यापारिक मामलों में धन का प्रवाह धीमा रह सकता है। जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्ण बातचीत से मसले हल होंगे।

कन्या

कार्यस्थल पर काम की गति कुछ धीमी रह सकती है। धैर्य से काम लें और व्यापार में जल्दबाजी में कोई अनुबंध न करें। अपने साथी के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखें।

तुला

कार्यस्थल पर सहकर्मियों की बातों का गलत अर्थ न निकालें। किसी भी सौदे में पारदर्शिता रखें। अनावश्यक शक या संवेदनशीलता से रिश्ते में खटास आ सकती है।

वृश्चिक

काम में सावधानी रखें, छोटी-सी चूक भारी पड़ सकती है। जोखिम भरे व्यापारिक सौदों से दूर रहें। अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय पार्टनर के दृष्टिकोण को समझें।

धनु

नौकरी में सकारात्मक दिन रहेगा। कारोबारी हैं तो बिना योजना के काम करने से देरी हो सकती है। मानसिक उलझन को पार्टनर पर न निकालें।

मकर

चरणबद्ध तरीके से काम पूरा करने से तनाव कम होगा। पुराने व्यावसायिक संपर्कों से लाभ होगा। भावनात्मक रूप से दूरी महसूस हो तो बातचीत का सहारा लें।

कुम्भ

कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बना रहेगा। कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे। कारोबार में बदलाव के अवसर मिलेंगे। संपत्ति या पुराने निवेश से आर्थिक लाभ के योग हैं।

मीन

कार्यक्षेत्र में नए अवसर और संभावनाएं आपका उत्साह बढ़ाएंगी। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे। पार्टनर के साथ समझदारी और प्रेम बढ़ेगा। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।

बॉलीवुड | मसाला

रजनीकांत की जेलर 2 ने रचा इतिहास 160 करोड़ रुपये की हुई ओटीटी डील

साउथ सिनेमा के वेटरन एक्टर रजनीकांत का नाम पिछले समय से उनकी आने वाली मोस्ट अवेटेड मूवी जेलर 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर के सीक्वल के तौर पर रजनीकांत की इस मूवी को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। इस बीच निर्देशक नेल्सन दिलीप की जेलर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि थिएटर रिलीज से पहले मेकर्स ने जेलर 2 की ओटीटी डील कर डाली है, जिसकी रकम आपके होश उड़ा सकती है।

आज के समय में देखा जाता है कि बड़े पर्दे पर फिल्म के आने से पहले उसके डिजिटल प्लेफॉर्म का सौदा कर लिया जाता है। रजनीकांत की जेलर 2 के मामले में भी ऐसा देखने को मिला है और सिनेमाघरों में रिलीज से पहले मेकर्स इसकी ओटीटी डील डन कर ली है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेलर 2 की हअक्ष डील इस साल की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है।

साथ ही, इसने थलपति विजय की फिल्म लियो का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यह OTT डील जेलर 2 के सिनेमाघरों में आने से कई महीने पहले ही हो गई है। हालांकि, अभी तक उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसने इसके राइट्स खरीदे हैं, लेकिन खबर है कि यह डील 160 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में हुई है।

ऐसे में रिलीज से पहले ही रजनीकांत की जेलर 2 एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। मालूम हो कि 3 साल पहले आई जेलर ने अपार सफलता हासिल की थी और वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 600 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। रजनीकांत के करियर की टॉप-5 ग्रॉसिंग मूवीज में इसका नाम दर्ज है।

पहले पार्ट की सक्सेस के बाद मेकर्स जेलर का सीक्वल ला रहे हैं। इसकी रिलीज डेट का एलान पहले ही किया जा चुका है, जिसके आधार पर 15 अक्टूबर 2026 को रजनीकांत स्टारर जेलर 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा।

बॉलीवुड | मन की बात

सनी देओल के मुस्लिम रोल सुनकर बंटवारा 1947 को नहीं मिल रहे थे निवेशक : संतोषी

बंटवारा 1947 के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने बताया है कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। इसकी वजह यह थी कि यह फिल्म बंटवारे के दौर पर आधारित है। इसमें सनी देओल ने एक मुस्लिम का किरदार निभाया है। संतोषी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखने वाले कई फाइनेंसर चाहते थे कि एक्टर पारंपरिक एक्शन रोल करें। फिल्ममेकर ने यह भी साफ किया कि कुछ रिपोर्ट्स और रिव्यू के उलट, देओल फिल्म में पाकिस्तानी किरदार नहीं निभा रहे हैं। इसके बजाय, वह एक ऐसे भारतीय मुस्लिम का किरदार निभा रहे हैं, जिसे बंटवारे के दौरान खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए पाकिस्तान जाने पर मजबूर होना पड़ा। संतोषी ने गलाटा इंडिया से बातचीत में बताया कि हालांकि इन्वेस्टर्स सनी देओल के साथ उनके कोलेबोरेशन को लेकर उत्साहित थे। मगर वे चाहते थे कि फिल्ममेकर वैसी ही एक्शन फिल्में बनाएं जैसी उनकी पिछली फिल्में घायल, दामिनी और घातक थीं। संतोषी ने बताया कि मुंबई में ज्यादातर इन्वेस्टर्स को जब पता चला कि सनी देओल और मैं एक फिल्म कर रहे हैं, तो वे चाहते थे कि मैं एक रेगुलर एक्शन फिल्म बनाऊं। वे ऐसी फिल्म के लिए तैयार नहीं थे जिसमें सनी एक मुस्लिम किरदार निभा रहे हों। जब इन्वेस्टर्स को पता चला कि देओल बंटवारे पर आधारित ड्रामा में एक मुस्लिम व्यक्ति के तौर पर गंभीर भूमिका निभाएंगे, तो उन्होंने बंटवारा 1947 को फंड देने से इनकार कर दिया। संतोषी ने कहा कि देओल ने पहले भी मुस्लिम किरदार निभाए होंगे, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार मिजाज और ट्रीटमेंट के मामले में अलग है। फिल्ममेकर ने कहा कि किरदार का सफर ही फिल्म का मुख्य हिस्सा है और उसे सिर्फ पाकिस्तानी कहना उसके बैकग्राउंड और हालात को कमतर आंकने जैसा होगा।

अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रोल में देख भड़के लोग

अंजलि अरोड़ा फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का टीजर और पोस्टर मेकर्स ने मंगलवार को रिलीज किया। इसके बाद से ही एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। कई यूजर्स अंजलि को माता सीता के रोल में कास्ट किए जाने पर मेकर्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा में अंजलि अरोड़ा सीता और देव शर्मा राम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें अंजलि को माता सीता के रूप में देखने के बाद यूजर्स भड़क उठे। अब वो इस फिल्म का और इसमें अंजलि को कास्ट किए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं।

इस मामले पर अंजलि को सोशल मीडिया में बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करने पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन सीता माता के किरदार के लिए यह गलत कास्टिंग है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया-मां सीता के रोल में सूर्पनखा?

इस फिल्म की तुलना फिल्म 'आदिपुरुष' से करते हुए यूजर ने लिखा, आदिपुरुष को सलाम। वहीं अन्य यूजर्स ने इसे तीन घंटे की इंस्टाग्राम रील बताया।

फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही अलग-अलग कारणों से इसकी आलोचना हो रही है। फिल्म की कास्टिंग के अलावा टीजर में दिखाए गए वीएफएक्स भी दर्शकों को कमजोर दिखाई दिए। कई यूजर्स ने इन वीएफएक्स को शर्मनाक बताया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की प्रस्तुती और म्यूजिक भी यूजर्स को उत्साहित नहीं कर सका।

इस फिल्म का निर्माण महोबिया फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। फिल्म को प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है। अजय कनौजिया की कंपनी एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने इसे पेश किया है। इसका निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है। फिल्म में अंजलि के अलावा शील वर्मा, रजनीश दुग्गल और निर्भय वाधवा भी अहम किरदारों में हैं।

यहां आईफोन से भी सस्ता बिक रहा है बंगला, कौड़ियों के दाम खरीद रहे लोग, भाग-भाग कर करवा रहे रजिस्ट्री!

दुनिया के कई देशों में घर खरीदना सपना बनकर रह जाता है। कीमतें आसमान छूती हैं और आम आदमी के लिए अपना घर बसाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जापान में एक बिल्कुल उलटी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहां लाखों घर सालों से खाली पड़े हैं। इन्हें जापानी भाषा में अकिया कहा जाता है। अब इन अकिया घरों की बिक्री जोरों पर है और कुछ तो इतने सस्ते हैं कि उनकी कीमत एक अच्छे आईफोन से भी कम बैठ रही है। लोग कौड़ियों के दाम में ये घर खरीदने के लिए भाग-भाग कर रजिस्ट्री करवा रहे हैं। जापान में अकिया की समस्या पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। देश की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और ग्रामीण इलाकों से युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि गांवों और छोटे कस्बों में लाखों घर खाली पड़ गए हैं। मालिक या तो गुजर चुके हैं या शहर में बस गए हैं और घर की देखभाल नहीं कर पा रहे। ऐसे में इन घरों को औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक जापान में ऐसे खाली घरों की संख्या कई लाखों में है और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इन घरों की कीमत उनके आकार, लोकेशन और हालत पर निर्भर करती है। कुछ घर पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं तो कुछ में थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। दूरदराज के इलाकों में जहां आबादी बहुत कम है वहां कुछ संपत्तियां बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। सोशल मीडिया और खबरों में दावा किया जा रहा है कि कुछ बंगले या घर आईफोन की कीमत से भी सस्ते में बिक रहे हैं। यही वजह है कि लोग इन घरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोग इस खबर को पढ़कर हैरान हैं। कई भारतीय यूजर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे जापान शिफ्ट होने के तरीके सर्च कर रहे हैं। सस्ता घर होने का लालच किसी को भी आकर्षित कर सकता है। लेकिन हकीकत सिर्फ कीमत तक सीमित नहीं है। इन घरों को खरीदने के बाद कई चुनौतियां भी आती हैं। सालों से खाली पड़े इन घरों में सबसे बड़ी चुनौती मरम्मत की है। जापानी सरकार और स्थानीय प्रशासन अकिया समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। कुछ जगहों पर खाली घरों को सस्ते में या कभी-कभी मुफ्त में देने की योजनाएं चलाई जाती हैं बशर्ते खरीदार वहां रहें और घर को ठीक रखें।

अजब-गजब | इस प्रोजेक्ट पर बर्बाद हो गये थे लाखों करोड़ रुपये

भारत में बसाया जा रहा था मिनी इटली, आज बना घोस्ट टाउन

भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के कई बड़े प्रोजेक्ट समय-समय पर लॉन्च होते रहे हैं। कुछ सफल रहे तो कई अधूरे रह गए और निवेशकों के पैसे फंस गए। इनमें से एक प्रमुख नाम है पुणे के पास लवासा प्रोजेक्ट का। इसे भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन बनाने का सपना देखा गया था। इटली के तटीय शहर पोर्टोफिनो की तर्ज पर डिजाइन किया गया यह टाउन आज घोस्ट टाउन जैसा दिखता है।

हजारों करोड़ रुपये का निवेश होने के बावजूद यहां मुट्ठीभर लोग रहते हैं और बेसिक सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। लवासा की कहानी दो दशक पहले शुरू हुई। महाराष्ट्र सरकार की हिल स्टेशन पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एचसीसी ने इसे विकसित करने का जिम्मा लिया था। अजित गुलाबचंद के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में मुलशी तालुका के आसपास फैला। वरसगांव बांध के बैकवाटर्स के किनारे रंग-बिरंगी इमारतें, लेकसाइड प्रॉमनेड, होटल, विला और आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बसाने की योजना थी। पांच टाउन और सात पहाड़ियों पर फैले इस प्रोजेक्ट में दो लाख लोगों के रहने की कल्पना की गई थी। लेकिन इसका अंत ऐसा होगा, किसी ने नहीं सोचा था।

शुरुआत में लवासा आकर्षण का केंद्र बना। पर्यटक यहां आने लगे। कुछ लोग विला

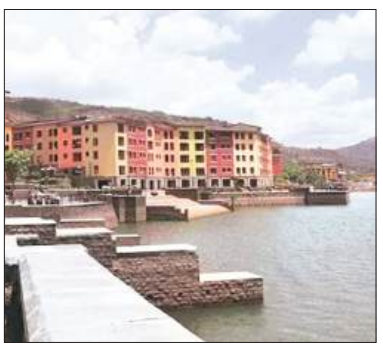

और अपार्टमेंट खरीदने लगे। इटालियन अंदाज की सड़कें, खुले स्थान और हरियाली ने इसे खास बनाया। लेकिन जल्द ही समस्याएं सामने आने लगीं। 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने निर्माण पर रोक लगा दी। आरोप था कि जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई थी। प्रोजेक्ट पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में था। पेड़ों की कटाई, ढलानों पर निर्माण और जल स्रोतों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठे। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कुछ समय बाद रोक हटी लेकिन प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई। जमीन अधिग्रहण को लेकर भी विवाद रहे। स्थानीय किसानों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की बातें उठीं। सीएजी रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी हुए। इन सबके बीच कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। 2018 के आसपास लवासा कॉर्पोरेशन दिवालिया प्रक्रिया में चली गई। वित्तीय लेनदारों के दावे हजारों करोड़ रुपये के थे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में मामला चला। कई रिवाइवल प्लान आए। 2023 में डार्विन प्लेटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्लान मंजूर हुआ लेकिन भुगतान संबंधी मुद्दों पर 2024 में उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर से नई बोली प्रक्रिया शुरू हुई। वेलस्पन और अन्य कंपनियों ने रुचि दिखाई लेकिन पर्यावरण मंजूरी और अन्य शर्तों के कारण मामला अभी भी उलझा हुआ है। आज लवासा की हालत देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म सेट छोड़कर चला गया हो। अधूरी इमारतें, खाली सड़कें, बंद दुकानें और वीरान माहौल। दासवे सर्कल इलाके में कुछ होटल, कैफे और गतिविधियां चलती हैं। कुछ लोग यहां रहते हैं। अनुमान है कि दो हजार से पांच हजार के बीच आबादी है। कई घर खरीदारों के पास चाबियां नहीं पहुंचीं। कुछ को कब्जा मिला लेकिन रखरखाव और सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। बरसात में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हुई हैं। पर्यटक अभी भी जिज्ञासावश यहां आते हैं। पहाड़, झील और रंगीन इमारतें सुंदर लगती हैं लेकिन जीवन का अभाव खलता है। कई लोग इसे शहर जो सांस लेना भूल गया कहते हैं।

अपने ही विभाग के आगे विवश हैं फणनवीस

सीएम के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र का नगर विकास विभाग मौन

» अजमेरा ग्रुप की कुप्रबंधन से लोगों को नहीं मिल रही रोशनी

» सिटी मॉल के पीवीआर में पोस्टरों से पाटकर किया अंधेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। भाजपा के दिग्गज नेता व महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फणनवीस जिनको अगले पीएम के रूप में चर्चा में भी देखा जा रहा है वे अपने राज्य के नगर विकास विभाग के आगे विवश हैं। दरअसल पिछले दिनों 4पीएम के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार व फिल्ममेकर संजय शर्मा ने अपने कार्यालय जो कि ओशिवारा में है वहां पर रोशनी की कमी की शिकायत सीएम व बीएमसी को की थी। उन्होंने बताया था सिटी मॉल में ओशिवारा के ऑफिस के सामने मिर्जापुर मूवी के पोस्टर खिड़कियों के सामने लगा दिए गये हैं। इसकी वजह से उसके पास के सारे ऑफ़िसों की प्राकृतिक रोशनी बंद हो गयी है। जब लोगों ने मॉल प्रबंधन से इसकों हटाने के लिए कहा तो प्रबंध तंत्र इन पोस्टरों को हटाने को तैयार नहीं हुआ।

सबसे बड़ी बात सीएम से शिकायत व आश्वासन के बाद भी सीएम के नगर विकास विभाग ने 72 घंटों बाद भी कोई कार्रवाई नही की। इसी से पता चलता है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों की पैठ कितनी गहरी है कि सीएम की भी नहीं सुनाता है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी की रोशनी नहीं रोक सकता है। सिटी मॉल ओशिवारा प्रबंधन व पीवीआर की मनमानी के चलते वहां के आस-पास के कार्यालय के लोग परेशान है। इस बाबत जब बीएमसी कमिश्नर को मेल किया गया तो बताया गया जांच कराई जा रही है। पर कई दिनों के बाद अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के बाद पता चला कि मुंबई के कई इलाकों में अवैध पार्किंग, होर्डिंग लगीं हैं। पर करोड़ो की अवैध की कमाई के चलते बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करता है।

पुलिस के सामने आश्वासन के बाद भी अजमेरा प्रबंध मुकरा

वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने जब इस समस्या के लिए सीएम देवेन्द्र फणनवीस को मेल से शिकायत की तो तुरंत उनके कार्यालय से जवाब आया कि आपकी समस्या के बारे में नगरविकास विभाग को जानकारी दे दी गई है आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। उसके मैंने पुलिस में भी शिकायत की। बाद कार्यालय में पुलिस आई। पुलिस ने कहा रोशनी बंद करना अनुचित है। अजमेरा के मैनेजर ने पुलिस के सामने कहा का तुरंत हट जाएगा। पर पुलिस के जाने के बाद वह मुकर गए बोले इस पोस्टर को हटा नहीं पाएंगे इससे काफी रेवेन्यू मिलता है।

अन्य लोगों ने भी सीएम से की गुहार

अन्य भुक्तभोगियों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को की है पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। बता दें सूत्रों से पता चला है कि इन पोस्टरों व प्रचार के लिए बहुत पैसा मिला है इस लिए वे इसने नहीं हटा रहे है। पर उनकी इस अंधेरगर्दी का शिकार वहां के लोग हो रहे हैं। मॉल व पीवीआर प्रबंधन की ओर से तो गुंडागर्दी जारी है। लोगों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फणनवीस तत्काल इन पोस्टरों को हटाने के आदेश देने की अपील की है। उधर पीड़ित लोगों का दावा है कि कुछ भी हो जाए बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि प्रचार कंपनी बहुत उन्हें उपकृत करती है।

बीएमसी ने भी किनारा किया

बेंगलुरु के एक बड़े वित्तीय घोटाले में भी फंसा है अजमेरा ग्रुप

अजमेरा ग्रुप से जुड़े विवाद का मुख्य मामला बेंगलुरु का एक बड़ा वित्तीय घोटाला (पोंजी स्कीम) है। जून 26 में, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने ठगी के शिकार निवेशकों को राहत देते हुए अजमेरा ग्रुप की कुर्क की गई 8.41 करोड़ रुपए की संपत्ति पीड़ितों को वापस लौटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया। अजमेरा ग्रुप और एमएफ एंटरप्राइजेज ने बिना किसी लाइसेंस या आरबीआई/सेबी की अनुमति के जनता से पैसे जमा करवाए। भरकम रिटर्न का झूठा लालच दिया गया था। आरोप था कि कुल 2500.6 करोड़ रुपए अवैध रूप से जुटाए गए, जिसमें से करीब 72.9 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस नहीं लौटाए गए और गबन कर लिए गए। प्रवर्तन निदेशालय 8.41 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

मुंबई में कई विवाद

मुंबई के पास कल्याण (पश्चिम) स्थि (योगीधाम क्षेत्र) में 18 दिसंबर 24 की रात को अगरबत्ती के धुएं को लेकर एक विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए थे और यह मामला राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में आया था। फ्लैट के बाहर अगरबत्ती जलाने और उसके धुएं को लेकर पड़ोसी लता कलविकटे और अखिलेश शुक्ला (तथा उनकी पत्नी गीता शुक्ला) के बीच बहस हुई थी। यह बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मुख्य आरोपी अखिलेश शुक्ला और बाहर से बुलाए गए लोगों ने स्थानीय मराठी परिवार (देशमुख परिवार) पर हमला किया, जिसमें अभिजीत देशमुख को सिर पर गंभीर चोटें आईं।

नृपेंद्र मिश्रा के फैसले के बिना कोई काम नहीं होता था : चंपत राय

» जारी की 20 पेज की चिट्ठी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी पद से दान में अनियमितताओं के आरोपों के बीच हटने को मजबूर हुए चंपत राय ने एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता वाली मंदिर निर्माण समिति ने सभी फैसलों को मंजूरी दी और उनकी मदद के लिए नियुक्तियां कीं। उन्होंने कहा कि मिश्रा ने अपनी पसंद के लोगों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति में शामिल किया। राय ने बताया कि उनमें से एक व्यक्ति छह साल में सिर्फ़ दो बार अयोध्या आया, और दूसरे से सिर्फ़ सुरक्षा से जुड़े सुझाव ही मांगे गए।

राय ने कहा कि तीसरा सदस्य नियमित था और हमेशा मिश्रा के साथ बैठकों में शामिल होता था। उन्होंने आगे कहा कि बैठकें हर महीने और कभी-कभी हर 15 दिन में होती थीं। राय ने ज़ोर देकर कहा कि समिति के पास पूरा अधिकार था। उन्होंने कहा कि समिति की मंजूरी के बिना कोई भी काम नहीं किया गया। राय ने उस पत्र में कहा अगर बाहर कोई फ़ैसला लिया गया, तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। अगर कुछ किया गया, तो उसे हटा दिया गया। यह पत्र वायरल हो गया है और समिति के कामकाज को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राय का कहना था कि मिश्रा ने निर्माण से जुड़े सभी मामलों में खुद को एकमात्र अधिकारी के तौर पर पेश किया, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि मंदिर उन्हीं की वजह से हकीकत बन पाया है। राय ने 2020 में कोविड महामारी के दौरान मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद उसके उद्घाटन को सुनिश्चित करने का श्रेय मिश्रा को दिया। राय ने लिखा यह पूरी तरह से नृपेंद्र जी के काम का नतीजा है।

महंगे खाने व सफर से लोग परेशान: जयराम

» कांग्रेस ने ई-20 नीति की तत्काल समीक्षा करने को कहा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र की ई20 नीति की तत्काल समीक्षा करने तथा उपभोक्ताओं को बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति के कारण जनता को ''महंगे खाने और महंगे सफर'' दोनों की कीमत चुकानी पड़ रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ''गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी, ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं हो सकती।

रमेश ने दावा किया कि एथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 25 लाख टन चीनी-लायक गन्ना एथेनॉल उत्पादन में चला गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति किलोग्राम और गुड़ की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। उन्होंने दावा किया कि चावल और मक्के का आटा भी क्रमशः 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत महंगा हुआ है, जबकि पशु आहार की कीमत में 10.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस महासचिव ने ई20 के कारण वाहनों के माइलेज और उनकी अनुकूलता को लेकर भी सवाल उठाए।

जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कार्य समिति ने 19 अगस्त को ई20 के कारण कम माइलेज, वाहनों की अनुकूलता, उपभोक्ताओं के सीमित विकल्प और पर्यावरणीय क्षति से जुड़े सवालों पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि ई20 नीति की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए और जनता को बिना इथेनॉल वाले विकल्प मिलने चाहिए। गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी, ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं हो सकती।

वायरल वीडियो देखकर विधायक मलिक ने की डिलीवरी बॉय की मदद

» भेंट किया नया मोबाइल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुजफ्फरनगर। चरथावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज मलिक ने प्रेमपुरी स्थित अपने आवास पर डिलीवरी बॉय विशाल को नया मोबाइल फोन भेंट कर उनकी परेशानी में सहयोग किया। गत दिनों डिलीवरी का कार्य करते समय विशाल का मोबाइल फोन पानी में गिर गया था और काफी तलाश के बावजूद वह नहीं मिल सका।

उनकी परेशानी और दुख से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो की जानकारी मिलने पर विधायक पंकज मलिक ने विशाल से संपर्क कर उन्हें अपने आवास पर बुलाया था।

टल सकता है भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा!

» बीसीबी की उम्मीदों को लग सकता है झटका, सितंबर में होनी है सीरीज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बांग्लादेश को बीसीसीआई एक बार फिर तगड़ा झटका दे सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा एक बार फिर टल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, तमीम का कहना है कि सीरीज को लेकर फिलहाल बीसीबी और बीसीसीआई के बीच बातचीत जारी है। तय कार्यक्रम के अनुसार, भारत को पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश का दौरा करना था, लेकिन इसे सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

बीसीबी ने जनवरी में बताया था कि भारतीय टीम ढाका और चट्टोग्राम में तीन वनडे और इतने ही टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। हालांकि, इस दौरे को लेकर अब तक बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, पहला वनडे तीन सितंबर से होना है। लेकिन इससे दो सप्ताह पहले तक इस बात पर संशय बना हुआ है कि सीरीज होगी भी या नहीं। तमीम ने कहा कि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। तमीम ने कहा, दोनों क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसकी तारीख में कुछ बदलाव हो सकता है। यह टूर्नामेंट मीरपुर में होना है, लेकिन इसे दो मिनट में बासुंधरा ग्राउंड में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर भारत का दौरा फाइनल होता है तो हम उस हिसाब से शेड्यूल रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में उस समय खटास पैदा हो गई जब कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। इसके बाद अमीनुल इस्लाम की अगुआई वाली बीसीबी ने टी20 विश्व कप के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया, जिसकी सह-मेजबानी भारत ने की थी।

जो रूट ने की सचिन के टेस्ट में अर्धशतकों की बराबरी

लीड्स। इंग्लैंड के नवनियुक्त टेस्ट कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की। रूट ने लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपने टेस्ट करियर का 68वां अर्धशतक लगाया। रूट ने इसके साथ ही टेस्ट में सर्वाधिक बार अर्धशतक लगाने के मामले में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। रूट अब सचिन के साथ टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। सचिन ने भी अपने करियर में 68 टेस्ट अर्धशतक लगाए थे। यानी रूट अगर एक भी अर्धशतक और लगा देते हैं तो वह इस मामले में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल 66 अर्धशतक के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर और पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 63 अर्धशतक लगाए हैं।

वंदे मातरम् की क्लास में फंस गयी बीजेपी!

कपिल सिब्बल के सवाल से उलट गयी राजनीति, बीजेपी को देते नहीं पड़ रहा जवाब, कांग्रेस से पूछा था पूरा क्यों नहीं गाया अब सवाल उठा खुद कितना गाया?

» सिब्बल के सवाल क्या पीएम मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई ने राजनीतिक कार्यक्रमों में गया पूरा वंदे मातरम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। वंदे मातरम पर कांग्रेस की परीक्षा लेने निकली बीजेपी के सामने अब इतिहास की कॉपी खुल गई है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सवालों की ऐसी घंटी बजा दी है कि कानों में सीटी बजने लगी है। कपिल सिब्बल के एक्स पर पोस्ट के बाद राष्ट्रवाद की क्लास लेने वाली बीजेपी अब खुद हाजिरी लगाने में उलझी दिखायी दे रही है। कपिल सिब्बल ने सवाल ही ऐसा पूछा कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए पूरा वंदेमातरम गाया? क्या पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई ने पूरा वंदेमातरम गीत गाया है।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वंदे मातरम के केवल दो अंतरे गाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। सिब्बल ने सवाल उठाया है कि जिस फैसले को आज कांग्रेस की गलती बताकर राष्ट्रवाद की राजनीति चमकाई जा रही है क्या उस कसौटी पर बीजेपी के बड़े नेता खुद भी खरे उतरते हैं। सिब्बल ने कहा है कि यदि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1937 के फैसले के तहत केवल दो अंतरे गाना एंटी नेशनल है तो फिर यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम् गाया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए हमेशा पूरा वंदे मातरम् गाया? उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले को एंटी नेशनल करार दिया जिसमें वंदे मातरम के दो अंतरे गाने की बात कही गई थी।

सिब्बल का तर्क है कि अगर बीजेपी आज इसी आधार पर कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रही है तो फिर उसे अपने नेताओं और अपनी सरकारों के रिकॉर्ड पर भी जवाब देना चाहिए। यानी अब वंदे मातरम् की सियासत में बहस कांग्रेस के 1937 के फैसले से निकलकर बीजेपी के दरवाजे तक पहुंच गई है। सवाल सीधा है राष्ट्रवाद की परीक्षा के नियम सबके लिए एक जैसे होंगे या फिर विपक्ष के लिए अलग और सत्ता पक्ष के लिए अलग?

मामला सिर्फ वंदे मातरम् का नहीं रहा

अब सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति में राष्ट्रभक्ति भी फुल वर्जन और शॉर्ट वर्जन में बांटी जाएगी? क्या देशप्रेम के लिए भी कोई प्लेलिस्ट बनेगी? क्या चुनाव आयोग से पहले कोई राष्ट्रभक्ति आयोग बनेगा? क्या नेताओं को मंच पर जाने से पहले साउंड टेस्ट देना होगा? माइक चेक वन टू थ्री वंदे मातरम पीछे से आवाज आएगी स्टॉप आपने दूसरी लाइन पर सांस क्यों ली? संदिग्ध मामला है। बीजेपी ने वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की अब उसी वंदे मातरम उससे पूछे गये सवालों पर बचती नजर आ रही है।

अब बीजेपी के समाने सवालों का आइना

वंदे मातरम की बहस में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने निकली बीजेपी के सामने सवालों का ऐसा आईना आ खड़ा हुआ कि पूरी राजनीतिक कहानी ही पलट गई। अब पूछा जाने लगा कि अगर पूरा गीत गाना ही राष्ट्रभक्ति का नया पैमाना है तो इतिहास के पन्नों में झांकने का अधिकार सिर्फ सत्ता पक्ष के पास क्यों हो। इस बार इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए कांग्रेस और दूसरे नेताओं ने सत्ता पक्ष की ओर से उछाले गये सवाल को वापस सत्ता पक्ष के पास भेज दिया। गौरतलब है कि जब सवाल वापस आता है तो वह व्हाट्सऐप फॉरवर्ड मैसेज की तरह नहीं आता।वह रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि भेजने वाले को वापस कर दिया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि वंदे मातरम पूरा क्यों नहीं गाया? अब सवाल बीजेपी के दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि पहले आप बताइए आपकी पूरी हिस्ट्री में किसने कितना गाया? और यही इस पूरी कहानी का असली मजा है। जिस राष्ट्रवाद को लेकर विपक्ष की क्लास लगाई जा रही थी उसी क्लास में अब मास्टर साहब की अपनी कॉपी चेक होने लगी है। जिस स्केल से कांग्रेस की देशभक्ति नापी जा रही थी वही स्केल घूमकर सत्ता पक्ष की मेज पर पहुंच गया है।

कांग्रेस से सवाल पूछा गया कि पूरा वंदे मातरम् क्यों नहीं गाया?

बीजेपी लंबे समय से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती चली आयी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही ताना बाना बुना गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सिर्फ दो छंद गाये जाने वाले वंदे मातरम के प्रस्ताव वाली लाइन को बीजेपी ने पकड़ लिया और राष्ट्रवाद के नैरेटिव में कांग्रेस को उलझाने के लिए इसे एंटी नेशनल बता दिया गया। सवाल पूछने वालों ने ऐसा माहौल बनाया कि मानो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने किसी गुप्त तहखाने से राष्ट्रभक्ति की अधूरी पंक्तियां बरामद कर ली हों। लगा कि अब देश की सारी समस्याएं किनारे रख दीजिए। महंगाई बाद में देखेंगे बेरोजगारी का नंबर बाद में आएगा। शिक्षा स्वास्थ्य, सड़क, किसान सब अपनी अपनी फाइल लेकर वेटिंग रूम में बैठें। पहले राष्ट्रभक्ति का सिगिंग टेस्ट होगा और नियम भी बड़े शानदार होंगे बीजेपी पूछेगी कितना गाया? विपक्ष जवाब देगा आपने कितना गाया? बीजेपी कहेगी मुद्दा मत भटकाइए विपक्ष कहेगा आईना देखिए!

भारतीय राजनीति में मुद्दा जरूरी है

राजनीति में विरोधी को घेरने के लिए मुद्दा चाहिए। मुद्दा नहीं मिले तो पुरानी फाइल खोलो फाइल में कुछ न मिले तो इतिहास की अलमारी खंगालो वहां भी कुछ न मिले तो किसी बयान की आधी लाइन पकड़ लो और अगर कुछ भी हाथ न आए तो राष्ट्रवाद की तुरही बजा दो। तुरही बजते ही पूरा माहौल बदल जाता है। अब बहस यह नहीं होती कि देश में क्या हो रहा है। बहस यह होती है कि देश से प्यार कौन ज्यादा करता है। और देशप्रेम की यह प्रतियोगिता बड़ी दिलचस्प है। इसमें जज ही खिलाड़ी है खिलाड़ी ही कमेंटेटर है कमेंटेटर ही अंपायर है और जरूरत पड़ने पर फैसला बदलने वाला थर्ड अंपायर भी वही।

पैलेट गन मामले में डीसीपी से मिले राहुल गांधी

» एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरने पर बैठे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुए पैलेट गन के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी ऑफिस पहुंचे। वहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने घायल छात्र का हवाला देते हुए इस मामले में डीसीपी से कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्हें डीसीपी के ऑफिस से निराश ही लौटना पड़ा। संसद मार्ग से बाहर आए राहुल गांधी ने कार्रवाई नहीं होने पर धरना शुरू कर दिया। डीसीपी के कार्यालय के बाहर ही राहुल गांधी का धरना चल रहा है। धरने में राहुल गांधी के साथ साहिल लोहचब भी हैं।

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने शुक्रवार को डीसीपी से मिलकर पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लेकिन उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुणे में केवल महिला श्रोताओं के लिए आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले एक वीडियो साझा कर विचार मांगे हैं। उन्होंने महिलाओं से उनके संघर्ष, सपनों, समाज के व्यवहार और हिंसा जैसी परिस्थितियों पर खुलकर विचार साझा करने का आह्वान किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि महिलाओं के सामने मौजूद परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए ऐसी चर्चा होना बेहद आवश्यक है। राहुल ने कहा कि भारतीय महिलाओं के सामने मौजूद परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की चर्चा जरूरी है। कांग्रेस नेता पुणे में अपना कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें केवल महिला श्रोता होंगी।

पुणे में केवल महिलाओं के लिए 'छात्रों की गूंज'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि पुणे में केवल महिलाओं के लिए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'उस कार्यक्रम की प्रस्तुति तैयार करते समय, मैंने अपनी टीम की महिलाओं से 20-30 मिनट का समय निकालकर इस पर अपने विचार साझा करने को कहा कि एक भारतीय महिला होने के नाते वे क्या महसूस करती हैं। उन्होंने इस बात पर विचार साझा किए कि वे भारतीय महिला होने के बारे में क्या महसूस करती हैं, समाज उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, अच्छी चीजें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं।

महिलाओं की प्रतिक्रियाएं भी पढ़कर सुनाई

उन्होंने कुछ महिलाओं की प्रतिक्रियाएं भी पढ़कर सुनाईं। वीडियो के साथ 'एक्स' पर पोस्ट में राहुल ने पूछा कि भारतीय महिला होने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, 'मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या महसूस करती हैं। समाज की नहीं, परिवार की नहीं, आपकी अपनी आवाज क्या कहती है? आपके संघर्ष, आपकी रुकावटें, आपका नजरिया और आपके सपने। आपकी कहानी क्या है? राहुल ने कहा, 'मुझे लगा कि यह एक अच्छा अभ्यास था, जिसने मुझे आपकी भावनाओं को समझने में मदद की। हमारी टीम ने तय किया कि क्यों न इसे सभी के लिए खोला जाए और उन महिलाओं से पूछा जाए, जो इस कार्यक्रम में आ रही हैं या इसे देखने जा रही हैं, कि वे एक भारतीय महिला होने के बारे में क्या महसूस करती हैं।

झारखंड में सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक

» हाईकोर्ट का राज्य सरकार से मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश

» अगली सुनवाई 15 सितंबर को

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रांची। झारखंड हाई कोर्ट से सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और चयनित कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अदालत ने झारखंड में सीजीएल परीक्षा और सीडीपीओ की नियुक्ति को रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट में सीजीएल परीक्षा रद करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अंतरिम राहत दी है। गुरुवार को भी तीन याचिकाओं पर राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 15 सितंबर 26 की तिथि निर्धारित की है। सरकार के जवाब आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर आगे की प्रशासनिक और कानूनी स्थिति क्या रहने वाली है। दूसरी ओर, झारखंड हाई कोर्ट में पीसीसीएफ नियुक्ति मामले को लेकर भी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि चूंकि अभी इस मामले में अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए इस पर सोमवार को विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4 पीएम** न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**